*The question was put and the motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN: I have received a notice from Shri Sanjay Singh. This matter had already been discussed in the House, so I am not allowing it.

---

## MATTERS RAISED WITH PERMISSION

### Environmental hazard due to poisonous gas being released from cement factories in Satna

**श्री अजय प्रताप सिंह** (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान सतना जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का सतना जिला वर्तमान में cement factories का हब बना चुका है। इन cement factories के कारण वहां पर प्रदूषण की समस्या एक चुनौती बनकर उभर रही है। इस प्रदूषण की समस्या के कारण वहां के निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो रही हैं, हृदय संबंधी बीमारी हो रही है, कैंसर जैसी बीमारी के भी वे शिकार हो रहे हैं। प्रदूषण का मानक, जो सामान्यत: सतना में PM 2.5 से लेकर PM 60 तक होना चाहिए, आज वह बढ़कर PM 200 से अधिक हो रहा है। प्रदूषण के नियंत्रण के लिए इन factories में जो प्रदूषणरोधी संयंत्र लगना चाहिए, वह किसी भी factory में नहीं लगा हुआ है। प्रदूषण के विरुद्ध अपने शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने के लिए पहले यहां पर स्थानीय निवासियों और कर्मचारियों को गुड़ बांटा जाता था, अब वह गुड़ बांटना भी बंद कर दिया गया है। इन factories में स्वास्थ्य के लिए जो अस्पताल या dispensary की व्यवस्था होनी चाहिए, वह व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है। सतना के पूर्व कलेक्टर श्री संतोष मिश्र ने प्रदूषण के निवारण के लिए एक निर्देश जारी किया था, लेकिन उनके स्थानांतरण के पश्चात उनका निर्देश भी हवा हो गया है और इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि इन factories में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रदूषण से पैदा होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए dispensary की व्यवस्था हो, अस्पताल की व्यवस्था हो, वहां पर प्रदूषणरोधी संयंत्र लगाए जाएं तथा वहां काम करने वाले कर्मचारियों और आस-पास के स्थानीय निवासियों को जिस तरीके से पूर्ववत गुड़ बांटा जाता था, वह प्रक्रिया फिर से प्रारम्भ हो, बहुत-बहुत धन्यवाद।

### Rehabilitation of BPL families staying at railway premises in Rayagada, Odisha

**श्री भास्कर राव नेक्कांति** (ओडिशा) : धन्यवाद चेयरमैन सर, आज मैं रेलवे के बारे में एक विषय उठाना चाहता हूं। वहां पर रायगड़ा division एक नया division बना है, इसके लिए मैं Government of India को धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूं कि वहां पर रेलवे की जगह

पर करीब, 2,000 labourers reside कर रहे हैं। Problem यह है कि रायगड़ा में गवर्नमेंट की जगह है ही नहीं, except railway land. पहले जो महाराजा, जयपुर थे, उस वक्त रेलवे ने जितनी जगह की मांग की थी, उतनी जमीन रेलवे को दे दी गयी थी, इसलिए रेलवे के पास बहुत जगह है। यहां तक कि आपके division के लिए जितनी जगह की जरूरत है, उसके बावजूद भी वहां पर बहुत सी जगह खाली पड़ी रहेगी। इसलिए मेरी रेलवे डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि कम से कम उनके लिए जितनी जरूरत हो, उतनी लैंड स्पेयर करे। जरूरत पड़ने पर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की लैंड रेलवे को किसी और जगह पर देने की व्यवस्था करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि जो ये 10 हजार लोग हैं, जो रेलवे की जगह पर reside करते हैं, यह सब लोग रायगड़ा टाउन पर निर्भर रहकर अपनी जीविका चला रहे हैं। इसीलिए उनको कंसिडर करने के लिए मेरा सुझाव है।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by Shri Bhaskar Rao Nekkanti.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Bhaskar Rao Nekkanti.

**श्री सभापति:** मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है, कृपया सदस्य इस विषय पर ध्यान दीजिए।

Railways is always growing. Railways need some space also. Rehabilitation is very important. I allowed you to ask for rehabilitation but not at the present site or next to the railway station, etc. This is becoming a tendency everywhere including my town. There is also this demand. Finally, at the end of it, at airports, you are seeing what is happening, like, in Mumbai airport and others. We must see to it that they are properly rehabilitated and their interests are taken care of. Now, Shri Rajmani Patel.

**Need to implement recommendations of the Koshyari Committee for the benefit of pensioners**

**श्री राजमणि पटेल** (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति जी, मैं एक बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि कोशियारी कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश लागू करने के संबंध में है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भविष्य निधि का 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक सरकार के खजाने में जमा है। पेंशनभोगियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। 24 वर्षों से करीब 6 करोड़ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसके खिलाफ कोशियारी कमेटी की रिपोर्ट लागू करने तथा हायर पेंशन दिए जाने की मांग को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन चलाया जा रहा है। वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1,000 रुपये प्रतिमाह यानी 33 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेंशन दी जा रही है, यह बहुत ही गंभीर विषय है। यह उनकी मेहनत और सम्मान का अपमान है, जिन्होंने